धीरज गुर्जन व खाचरियावास की मौजूदगी में भीलवाड़ा में ''फसल मुआवजा जन अधिकार आंदोलन'' शुरु

अतिवृष्टि से खराब हुई फसलों पर तुरंत मुआवजा दिलाने की मांग की

भीलवाड़ा । जिले के किसानों की बर्बाद फसल और जनता की बुनियादी समस्याओं को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा आज ''फसल मुआवजा जन अधिकार आंदोलन'' की शुरुआत की गई। इस आंदोलन का नेतृत्व कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर के साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, प्रहलाद गुंजल ने की। खटिक छात्रावास, अहिंसा सर्किल में जनसभा के आयोजन करने के बाद रैली के रूप में सांगानेरी गेट, रामस्नेही अस्पताल, श्री गेस्ट हाउस चौराहा, मंगला चौक, भीमगंज चौकी, गोल प्याऊ चौराहा और रेलवे स्टेशन होते हुए जिला न्यायालय के सामने से कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां किसानों की ओर से जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा सौंपा।

भीलवाड़ा जिले के किसानों की बर्बाद फसल और जनता की बुनियादी समस्याओं को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा आज ''फसल मुआवजा जन अधिकार आंदोलन'' की शुरुआत की।

- जनसभा के आयोजन करने के बाद रैली के रूप में सांगानेरी गेट, रामस्नेही अस्पताल, श्री गेस्ट हाउस चौराहा, मंगला चौक, भीमगंज चौकी, गोल प्याऊ चौराहा और रेलवे स्टेशन होते हुए जिला न्यायालय के सामने से कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां किसानों की ओर से जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा

पूर्व मंत्री गुर्जर ने बताया कि आंदोलन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता और किसान मिलकर सरकार से पाँच सूत्रीय माँगों को लेकर ज्ञापन सौंपने, जिसमें जिलेभर में अतिवृष्टि से खराब हुई फसलों की घोषणा कर किसानों को तुरंत मुआवजा दिलाना, सरपंचों को मिले न्यायालय आदेशों की पालना सुनिश्चित कराना, पंचायत परिसीमन में जनता की भावनाओं का ध्यान रखना, विद्यालयों में जर्जर भवन व शौचालयों की मरम्मत कर बच्चों की सुरक्षा करना तथा भीलवाडा शहर में सीवरेज और सड़क निर्माण कार्यों से उत्पन्न अव्यवस्था को दूर करना प्रमुख बिंदु हैं। कांग्रेस और किसानों के आंदोलन को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए हैं। शहर के मुख्य मार्गों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया और जुलूस मार्ग पर विशेष निगरानी रखी गई ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या बाधा उत्पन्न न हो। हजारों की संख्या में किसान जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई।

आश्वासन पर किसानों का धरना समाप्त

गुडामालानी । उपखंड मुख्यालय पर भारतीय किसान संघ के बैनर तले तहसील परिसर के सामने किसानों द्वारा अनिश्चितकालीन धरना तहसील कार्यालय के सामने दिया जा रहा था। धरना स्थल पर उपखंड अधिकारी केशव कुमार मीणा, पुलिस उपाधीक्षक सुखाराम विश्नोई, प्रधान बिजलाराम चौहान,विधुत विभाग अधिकारी देवेन्द्र कच्छवाह पहुंचकर किसानों से वार्तालाप कर आश्वासन दिया।

तहसील अध्यक्ष खेताराम सियाग एवं जिला मंत्री दिनेश पटेल ने बताया कि चार दिनों से मुख्यालय पर किसानों द्वारा रबी वर्ष 2022 एवं 2023 में ओलावृष्टि होने के कारण पुरे क्षेत्र में ईसबगोल व जीरे की फसल के साथ अन्य किस्म की फसलें अत्यंत खराबा होने के बावजूद भी अभी तक अनुदान राशि नहीं मिली एवं रबी एवं खरीफ सीजन की बकाया सब्सिडी और आदान अनुदान राशि सहित विभिन्न मांगों को लेकर भारतीय किसान संघ के तत्वावधान में धरना दिया जा रहा था। इस दौरान स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर आकर जिला स्तर पर उच्च अधिकारियों से बात कर किसानों से वार्तालाप कर 15 दिनों तक उनके मांग को पुरा करनी बात कहने पर सभी किसानों ने धरना समाप्त किया। उपखंड अधिकारी केशव कुमार मीणा ने कहा कि किसान अपने अपने क्षेत्र में सरकार द्वारा लगाए जा रहे कैम्प में जाकर उसका फायदा लेवे। वही किसानों के आने वाली समस्याओं का समाधान होने कि बात कही। पुलिस उपाधीक्षक सुखाराम विश्नोई ने कहा कि नशा मुक्ति को लेकर पुलिस प्रशासन अपनी ओर से कार्रवाई कर रहा है।

भिवाड़ी में जलभराव निस्तारण को लेकर मंत्री की उद्योगपतियों से चर्चा

मंत्री ने उद्योगपतियों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सजग भी किया

अलवर । केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री एवं अलवर सांसद भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में शुक्रवार को रिको गेस्ट हाउस सभागार, भिवाडी में उद्योगपतियों एवं विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में भिवाडी जलभराव की समस्या के निस्तारण को लेकर व्यापक चर्चा हुई। इस दौरान मंत्री ने उद्योगपतियों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सजग करते हुए अपशिष्ट जल प्रबंधन एवं उपचार की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने पर बल दिया। इससे पूर्व केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने केंद्र एवं राज्य स्तर पर उच्च स्तरीय बैठक भी ली, जिसमें भिवाडी जलभराव समाधान के संबंध में व्यापक चर्चा की गई। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने औद्योगिक क्षेत्रों में अपशिष्ट जल प्रबंधन को लेकर आयोजित बैठक में सीईटीपी (सेंट्रल इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट) की प्रभावी मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि औद्योगिक इकाइयों के उत्पादन के अनुरूप एफ्लूएंट जल की सघन मॉनिटरिंग की जाए और किसी भी परिस्थिति में उपचारित किए बिना अपशिष्ट जल को खुली नालियों में नहीं छोड़ा जाए। उन्होंने उद्योगपतियों को उनके दायित्वों से अवगत कराते हुए सीईटीपी के माध्यम से ही जल का शोधन सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

मंत्री भूपेंद्र यादव ने केंद्रीय उच्च स्तरीय बैठकों के बाद भिवाडी में ली विभिन्न विभागों एवं उद्योगपतियों की बैठक ली।

बैठक में विशेषज्ञों ने भिवाडी जलभराव की समस्या के निस्तारण हेतु प्रस्तावित डीपीआर पर विस्तार से जानकारी दी। इसमें भिवाडी क्षेत्र के घरेलू जल, औद्योगिक अपशिष्ट जल और वर्षा जल का पृथक्करण कर उपचारित जल को औद्योगिक इकाइयों को पुन: उपयोग हेतु उपलब्ध कराने का प्रस्ताव शामिल है। उन्होंने बताया कि औद्योगिक इकाइयों के दूषित जल उपचार हेतु 6 एमएलडी क्षमता की सीईटीपी पहले से स्थापित है, जबकि 34 एमएलडी क्षमता का एसटीपी निर्माणाधीन है। इसे एडिशनल और टर्शरी ट्रीटमेंट तकनीक से आधुनिक बनाकर औद्योगिक इकाइयों के पैरामीटर के आधार पर पानी उपलब्ध कराया जाएगा, जिसका उपयोग औद्योगिक इकाइयों में पुन: किया जा सके। केंद्रीय मंत्री ने औद्योगिक इकाइयों को अपने जल उपयोग के पैरामीटर साझा करने के निर्देश दिए ताकि एसटीपी को अपठोड कर गुणवत्ता के अनुरूप पानी सप्लाई किया जा सके। बैठक में बताया गया कि भिवाडी एवं चौपानकी औद्योगिक क्षेत्रों में लगभग 10.2 एमएलडी पानी का उपयोग हो रहा है। आगामी योजना के तहत एसटीपी से उपचारित जल को औद्योगिक इकाइयों को उपलब्ध कराने के साथ-साथ शेष जल को कृत्रिम झील और सारेखुर्द बांध तक पहुँचाया जाएगा।

ग्रामीणों ने किया सेवा शिविर का बहिष्कार

पोकरण । विधानसभा क्षेत्र में ओरण, गोचर, तालाब एवं आगोर की भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने की मांग को लेकर ग्रामीणों में भारी नाराजगी है। ग्राम पंचायत आसकन्द्रा में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर का ग्रामीणों ने सामूहिक बहिष्कार किया।

ग्रामीणों का कहना है कि जब तक उनकी वर्षों पुरानी मांगों पर कार्रवाई नहीं होती, तब तक वे किसी भी प्रशासनिक शिविर में भाग नहीं लेंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मांगें पूरी नहीं हुईं, तो पूरे जैसलमेर जिले के ग्रामीण सेवा शिविरों का बहिष्कार किया जाएगा। गुरुवार को सुबह से शाम तक ग्राम पंचायत का एक व्यक्ति ने शिविर पांडाल में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई, ग्रामीणों की मुख्य मांगें चारागाह भूमि सुरक्षित करना - गाँव के मवेशियों के लिए पारंपरिक चरागाह (गोचर व ओरण) की भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जाए, ताकि इन पर अतिक्रमण न हो। गाँव के तालाब, नाडी व आगोर को सुरक्षित दर्ज कर उनकी सफाई और संरक्षण की व्यवस्था की जाए। सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर हो रहे कच्चे-पक्के अतिक्रमण तुरंत हटाए जाएँ।

मृतक की विधवा को तीन वर्ष बाद न्याय मिला

20 लाख रु. मुआवजा देने के आदेश

जालोर । जिला उपभोक्ता आयोग जालोर के अध्यक्ष घनश्याम यादव ने बीमा कंपनी को सेवा में त्रुटि का दोषी मानते हुए मृतक की विधवा को बीमा क्लेम की राशि बीस लाख रुपए मय ब्याज देने का आदेश सुनाया है। साथ ही बीमा कंपनी पर एक लाख सात हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

परिवादी सीतादेवी पत्नि धनाराम चैधरी, निवासी कारलू ने परिवाद पेश कर बताया कि परिवादीयां के पति धनाराम द्वारा बीमा कम्पनी एस.बी.आई. जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लि. से एक व्यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसी एक वर्ष की अवधि के लिए ली थी, जिसके लिए परिवादीयां के पति द्वारा एसबीआई बीमा कम्पनी को एक हजार रुपये का भुगतान किया था। 14 मार्च 2020 को परिवादीया के पति अपनी स्कूटी से कारलू से शिवगढ जा रहे थे तो अचानक स्कूटी से गिरने से उनके सिर में गहरी चोट आई, जिससे दौराने इलाज उनकी मौत हो गई। परिवादीया ने एक क्लेम सम्पूर्ण दस्तावेजों सहित नॉमिनी होने से एसबीआई बीमा कम्पनी के समक्ष पेश किया। बीमा कंपनी ने अपने पत्र 18 फरवरी 2021 के द्वारा क्लेम को खारिज किये जाने की सूचना दी। जिस पर परिवादिया ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से विधिक नोटिस भेजा। जिसका बीमा कंपनी ने जवाब भेजकर क्लेम देने से इनकार कर दिया। इस प्रकार अप्रार्थी बीमा कम्पनी ने केवल मात्र सुनी सुनाई बातों को आधार मानकर बीमा क्लेम को गलत रूप से खारिज किया है।

परिवादिया ने आयोग से क्लेम राशि एवं हर्जाना दिलाने की मांग की। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष घनश्याम यादव एवं सदस्य निरंजन शर्मा ने तथ्यों और बीमा कंपनी के जवाब आदि तथ्यों का अवलोकन करने के पश्चात बीमा कंपनी जरिए प्रबंध संचालक को सेवा में त्रुटि को दोषी मानते हुए 45 दिन के भीतर बीमा क्लेम राशि 20 लाख रुपये परिवाद प्रस्तुत करने की दिनांक से ब्याज सहित देने का आदेश दिया है।

कटसुरा में पट्टे वितरित किये

मदनगंज-किशनगढ़(निस)। निकटवर्ती गांव कटसुरा में सेवा शिविर के दौरान केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री के पुत्र भाजपा युवा नेता सुभाष चौधरी ने शामिल होकर पात्र परिवारों को पट्टे वितरण किये। पट्टे मिलने पर गांव वालों ने हर्ष व्यक्त किया। युवा नेता चौधरी ने कहा कि शिविरों के माध्यम से अंतिम पायदान पर खडे व्यक्ति को भी सरकारी योजनाओं को लाभ मिल रहा है, सभी जायज समस्याओं का मौके पर ही त्वरित समाधान किया जायेगा। उन्होंने श्रीराम गौशाला में बोरवेल का शुभारंभ कर गौमाता हरा चारा व गुड खिलाकर पीएम मोदी का जन्मदिन मनाया। श्रीराम गौशाला संतो द्वारा केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी को पानी के लिये बोरवेल की आवश्यकता बताने पर तत्काल ट्यूबवेल स्वीकृत कर दिया। इस दौरान भाजपा सिलोरा मण्डल अध्यक्ष लक्ष्मण पहलवान, सुरसुरा मण्डल अध्यक्ष कुलदीप सुनारीवाल, पूर्व मण्डल अध्यक्ष रामावतार वैष्णव, मण्डल महामंत्री मदन जांगिड, गणेश प्रजापत, राजेन्द्र खोरवाल, राजकिशोर सैनी, प्रधाननाथ योगी, कमल कुमावत, सांवरलाल योगी, रामनिवास सैनी, सहित अनेक संतगण, भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं आमजन उपस्थित रहें।

'अजमेर विधानसभा के वोट चोरी की भी हो जांच'

अजमेर (कासं)। गंज स्थित जनकपुरी में शुक्रवार को अजमेर उत्तर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान का शुभारम्भ हुआ। मुख्य अतिथि हस्ताक्षर अभियान के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के समन्वयक रणजीत चंदेलिया व पूर्व आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर के बैनर पर अपने हस्ताक्षर कर अभियान का शुभारम्भ किया। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष पूर्व विधायक डॉ राजकुमार जयपाल, पूर्व विधायक डॉ श्री गोपाल बाहेती, डेयरी चेयरमैन रामचन्द्र चौधरी, कांठोस प्रत्याशी रहे महेंद्र सिंह रलावता, नगर निगम अजमेर में नेता प्रतिपक्ष द्रोपदी कोली सहित अन्य कांग्रेस नेताओं ने कहा कि देश भर में वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान की आंधी चल रही है। भाजपा की मोदी सरकार और चुनाव आयोग दोनों मिलीभगत कर वोट चोरी कर रहे है भाजपा को चुनाव जीता कर उनकी सरकार बना रहे है। कर्नाटक और महाराष्ट्र चुनाव में वोटों की चोरी सामने आई है, उन्होंने कहा कि जहां कांठोस चुनाव जीतती है, वहां वोट चोरी ज्यादा हुए है। वोट चोरी का लोकसभा नेता विपक्ष राहुल गांधी ने पत्रकार वार्ता करके दो बार खुलासा किया। बावजूद इसके न तो चुनाव आयोग के कानों पर जू रेंग रही है न ही मोदी सरकार इस पर कोई एक्शन ले रही है। पूर्व आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने कहा कि अजमेर के उत्तर विधानसभा व दक्षिण विधानसभा सहित जिले में हम बहुत ही कम वोटो के अंतर से हारे है। ऐसे में अजमेर के चुनावो की वोट चोरी की जांच की मांग करते है। हस्ताक्षर अभियान के शुभारंभ कार्यक्रम में मौजूद अजमेर उत्तर के ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष शैलेंद्र अठावाल व वाहिद मोहम्मद, अजमेर दक्षिण के ब्लॉक कांग्रेस चंदन सिंह व लक्ष्मी धोलखेडिया, महिला कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष प्रियंका चौधरी, शहर महिला कांग्रेस अध्यक्ष पार्षद लक्ष्मी बुंदेल, शहर कांग्रेस महासचिव पार्षद नौरत गुजर, उपाध्यक्ष गुलाम मुस्तफा, आदि ने अभियान के तहत हस्ताक्षर किए और कार्यकर्ताओं को संबोधित कर वोटो की चोरी रोकने के लिए जुटने का आव्हान किया।

अजमेर उत्तर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान का शुभारम्भ हुआ।

आपसी समझौते और प्रशासनिक तत्परता से सुलझा भूमि प्रकरण

भीलवाडा । राज्य सरकार एवं जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू के निर्देशन में उपखंड क्षेत्र बिजौलियां में ग्रामीण सेवा शिविर 2025 का आयोजन सुनिश्चित किया जा रहा है। इसी क्रम में 19 सितम्बर को ग्राम पंचायत मकरेडी में उपखंड अधिकारी बिजौलियां की अध्यक्षता में शिविर का सफल आयोजन संपन्न हुआ। इस शिविर के दौरान ठाम कामा की खाता संख्या 94, कुल रकबा 0.7284 हैक्टेयर भूमि के बंटवारे से संबंधित एक मामला प्रस्तुत किया गया, जिसमें श्रीमती मांगी देवी पत्नी भोलुराम निवासी सलावटिया, रामकन्या पुत्री शंभुगिरी निवासी सलावटिया, तथा ललित कुमार पुत्र रतनलाल निवासी माण्डलगढ़ द्वारा एक संयुक्त लिखित आवेदन शिविर प्रभारी को सौंपा गया। प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए शिविर प्रभारी एवं उपखंड अधिकारी के निर्देशन में तहसीलदार बिजोलिया द्वारा दोनों पक्षों की सहमति से मौके पर ही दस्तावेजों की समुचित जांच की गई तथा नियमानुसार आदेश पारित कर त्वरित समाधान सुनिश्चित किया गया। इस शीघ्र और निष्पक्ष कार्रवाई के फलस्वरूप न केवल संबंधित पक्षों में संतोष का वातावरण बना, बल्कि उपस्थित ग्रामीणजनों ने प्रशासन की पारदर्शी एवं समाधान केंद्रित कार्यशैली की सराहना करते हुए राज्य सरकार एवं उपखंड प्रशासन के प्रति अपना आभार व्यक्त किया।

परीक्षा केन्द्रों पर भारी भीड़ रही

भीलवाड़ा। चतुर्थ श्रेणी भर्ती में परीक्षा देने आए अभ्यर्थियों का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। पद के बजाय सरकारी नौकरी के सपने को सच करने के लिए शुक्रवार सुबह से ही युवाओं की भारी भीड़ केंद्रों पर देखने को मिली। इसके चलते परीक्षा केंद्रों पर भी जबरदस्त उपस्थिति देखने को मिली। शहर में 21 परीक्षा केंद्र बनाए गए है जहां पूरा इंतजाम किया हुआ था। परीक्षा देने आए अभ्यर्थियों की तलाशी अभियान पुरानी परीक्षाओं के तरह ही रहा।

शिविर में अव्यवस्थाएं मिलने पर भड़के कलेक्टर

डीडवाना । जिला मुख्यालय स्थित नगर परिषद में जारी शहरी सेवा शिविर का आज जिला कलेक्टर डॉ. महेंद्र खडगावत ने आज शाम आकस्मिक निरीक्षण किया। शिविर में अचानक जिला कलक्टर के पहुंचने पर मौजूद कार्मिकों में हड़बड़ी मच गई। वहीं निरीक्षण में कई अव्यवस्थाएं पाई गई, जिस पर जिला कलेक्टर ने गहरी नाराजगी जताई। साथ ही शिविर में अनेक विभागीय अधिकारी मौजूद नहीं मिले, बल्कि उनके स्थान पर अधीनस्थ कर्मचारी ही मौजूद मिले। इसे जिला कलेक्टर ने गंभीर लापरवाही बताया, साथ ही सभी अधिकारियों को शिविर में मौजूद रहकर जनता की समस्याओं का तत्काल समाधान करने और उनकी समस्याओं की सुनवाई करने के निर्देश दिए। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने शिविर में उपस्थित आम जनता से भी संवाद किया और उनकी समस्या सुनकर संबंधित विभागों को निर्देशित किया। जिला कलेक्टर ने कहा कि उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा पारदर्शी एवं संवेदनशील प्रशासन की परिकल्पना के तहत आमजन की समस्याओं की सुनवाई एवं त्वरित समाधान के लिए इन शिविरों का आयोजन किया है, ताकि जनता की मांगों व समस्याओं का तत्काल समाधान किया जा सके। उन्होंने कहा कि शिविर में किसी भी प्रकार की लापरवाही और शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर कोई कर्मचारी लापरवाही करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ तुरंत कड़ी कार्रवाई की जाएगा।

- शिविर में मौजूद नहीं मिले कई विभागीय अधिकारी
- विभागीय कार्मिकों को जनता की समस्याओं का तत्काल समाधान करने के निर्देश
- डीएम बोले, लापरवाही और शिथिलता नहीं की जाएगी बर्दाश्त

मेड़ता सहित पूरे जिले में धर्मांतरण नियंत्रण कानून को लेकर हिन्दू संगठनों में उत्साह

मेड़ता सिटी । राजस्थान सरकार द्वारा जबरन या प्रलोभन के माध्यम से होने वाले धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए नया कानून बनाए जाने के बाद मेडता क्षेत्र में विश्व हिंदू परिषद और हिंदू समाज के बीच उत्साह का माहौल देखने को मिला।

इसको लेकर आज विश्व हिन्दू परिषद के नेतृत्व में विभिन संगठनो ने मुख्य मंत्री के नाम उपखण्ड अधिकारी को धन्यवाद पत्र सौंपा। विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2025 बनाने के लिए अभिनंदन मुख्य मंत्री और सरकार का धन्यवाद ज्ञापित किया। राजस्थान हमेशा से वीरों, महापुरुषों और संतों की धरती है। धर्म, संस्कृति और देश की रक्षा के लिए राजस्थान के संघर्ष का इतिहास स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। यह पावन धरती दुर्भाग्य से लंबे समय से अवैध धर्मांतरण और लव जिहाद के षडयंत्रों से त्रस्त है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इन षड्यंत्र पर अंकुश लगना चाहिए था लेकिन इन षडयंत्रों के वीभत्स स्वरूप कई बार सामने आते रहे हैं। राजस्थान की धर्म प्राण जनता इससे पीड़ित है। राजस्थान का धर्म प्रेमी समाज विभिन्न सरकारों से बार-बार इन षडयंत्रों पर रोक लगाने के लिए प्रभावी कानून बनाने की मांग करता रहा है लेकिन वे वोट बैंक से प्रेरित घृणित राजनीति के चलते इन राष्ट्र विरोधी षडयंत्रों पर रोक लगाने की जगह इनको प्रश्रय देते रहे।

जिला प्रचार प्रमुख जितेंद्र गहलोत गहलोत ने कहा कि एक लोकप्रिय जन प्रतिनिधि और कुशल प्रशासक होने के नाते मुख्य मंत्री जी ने इस समस्या की भीषणता को समझा और जन भावनाओं और कानून व्यवस्थाओं की संवेदनशीलता को समझते हुए विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2025 बनाया। इसके लिए समस्त राजस्थान की जनता सरकार का अभिनंदन करती है और विश्वास व्यक्त करती है कि राजस्थान को मानवता के विरुद्ध इस सबसे बड़े अपराध से मुक्ति मिलेगी। अब राजस्थान के समाज को यह विश्वास हो रहा है कि वह अपनी आस्थाओं के अनुसार स्वतंत्रता पूर्वक और निर्भीक होकर अपना जीवन यापन कर सकेगा। राजस्थान की जनता अवैध धर्मांतरण और लव जिहाद के विरुद्ध इस संघर्ष में आपका सहयोग देने के लिए संकल्प व्यक्त करती है और विश्वास करती है कि मजबूत सरकार तथा मजबूत समाज दोनों मिलकर राजस्थान की पवित्र धरती को इन षडयंत्रों से मुक्त करेंगे। कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त करते हुए इसे सम्पूर्ण हिंदू समाज के हित में एक ऐतिहासिक कदम बताया। इस मौके पर वीएचपी जिला अध्यक्ष नवरत्न पंवार, जिला मंत्री ओमप्रकाश सोनी, छतरी धाम महंत संत हरिनारायण शास्त्री, वीएचपी जिला प्रचार प्रमुख जितेन्द्र गहलोत, वीएचपी जिला कौषध्यक्ष गजानंद तिवारी, पालिका अध्यक्ष शोभा लाहोटी, भाजपा जिला उपाध्यक्ष कल्पना चौहान, पूर्व चेयरमेन पवन परतानी, गजेंद्र सिंह, प्रखंड प्रचार प्रमुख चंद्र प्रकाश जांगिड, धर्म जागरण प्रमुख श्रवण कुमार चौधरी, विकास कुमार दायमा, धनराज सोनी, विनोद कुमार, कन्हैलाल सोनी, ओमप्रकाश बाता, लोक अभियोजक अभिमन्यु शर्मा, अवतार सिंह, मंडल सह कौशाध्यक्ष रवींद्र गहलोत सहित अनेक पदाधिकारी और प्रतिनिधी मौजूद रहे।

विश्व हिन्दू परिषद के नेतृत्व में विभिन संगठनों ने मुख्यमंत्री के नाम उपखण्ड अधिकारी को धन्यवाद पत्र सौंपा।

- विश्व हिंदू परिषद और अन्य संगठनों ने इस कानून का समर्थन जताया

भरतपुर में परीक्षा देने पहुंचे स्टूडेंट्स की आस्तीन काटी

भरतपुर (निस)। भरतपुर में आज से ग्रेड फोर्थ सीधी भर्ती परीक्षा शुरू हो चुकी है। इसके लिए जिले में 52 सेंटर बनाए गए हैं। तीन दिन तक रोज 2 पारियों में यह एग्जाम होगा। पहली पारी के पेपर के लिए सुबह 9 बजे से ही सभी सेंटर के गेट बंद कर दिए गए। 9 बजे के बाद किसी भी अभ्यर्थी को सेंटर के अंदर एंट्री नहीं दी गई। गहनता से चेकिंग के बाद भी सभी अभ्यर्थियों को सेंटर में एंट्री दी गई। महिलाओं के कानों के कुण्डल, गले की चेन उतरवाई गई। वहीं व्यक्तियों के फूल स्लीव्स वालों कपड़ों के बाजू काटे गए। जींस के बटन हाथ के धागे भी काटे गए। बायोमेट्रिक प्रजेंस के बाद ही सभी अभ्यर्थियों को एंट्री दी गई। इन 3 दिन में 96 हजार से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। यह परीक्षा 6 चरणों में आयोजित की जाएगी। पहले चरण में 15 हजार 200 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। दूसरी पारी का पेपर 3 बजे से शुरू हुआ। 2 बजे के बाद ही परीक्षा सेंटर के गेट बंद कर दिए गए। शाम 5 बजे दूसरी पारी की परीक्षा छूटेगी। पहली पारी का पेपर ख़त्म होने के बाद बस स्टैंड पर अभ्यर्थियों की भीड़ देखने को मिली। अभ्यर्थियों में बस की सीट मिलने को लेकर होड़ देखी गई।

3 दिन के अंदर भरतपुर में लगभग 96 हजार से ज्यादा अभ्यर्थी 6 चरणों में पेपर देंगे। हर दिन 32 हजार अभ्यर्थी पेपर देंगे। इस दौरान ई-मित्र और साइबर कैफे पर पुलिस निगरानी रखेगी। इसके अलावा शहर के मुख्य चौराहे, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर भी पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। पुलिस ने शहर के होटल, लॉज, धर्मशालाओं की जांच की है। जिला परिवहन अधिकारी ने प्राईवेट बस संचालकों, ऑटो संचालकों, ई-रिक्शा यूनियनों की बैठक लेकर उन्हें परीक्षार्थियों से मनमाना किराया वसूल नहीं करने के लिए पाबन्द किया गया है। ट्रेनों में कोच बढ़ाये गए हैं। जयपुर बयाना ट्रैन को भरतपुर तक किया गया है। परीक्षा सेंटर के लिए चिकित्सा विभाग की दो टीमें नियुक्त की गई हैं। एक टीम कलेक्ट्रेट कार्यालय के नियंत्रण कक्ष में रहेगी।